There is a proposal to have a Cantonment in Shillong but they said 'We do not want this Cantonment also.' So the fears have gone to such an extent. So we have to allay their fears and apprehensions. That is why an Act has been promulgated to ban completely purchase of land from a tribal by a non-tribal.

There were threats held out by some of the tribal people to encourage or to tell the landlords to evict the Bengali tenants and the Nepali tenants who are working in their fields. For that purpose also, the Meghalaya Government is enacting a law. These are the fears on both sides. And this matter has to be gone into as this is such a complex problem. We may not be able to give a sort of a direct solution for this. The Prime Minister also said that.

Deaths due to Communal Disturbances

*38. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the annual rate of deaths due to communal disturbances during the years 1966—77 and 1977—1979;

(b) whether these comparative figures show a decline; and

(c) if so, the reasons thereof?

गृह मंत्री (श्री ज़ैल सिंह): (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

साम्प्रदायिक झगड़ों में मारे गए व्यक्तियों की 1966 से 1979 तक का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1966 . . .	45
1967 . . .	251
1968 . .	133
1969 . . .	674
1970 . . .	298
1971 . . .	103
1972 . . .	70
1973 . . .	72
1974 . . .	87
1975 . . .	33
1976 . . .	39
1977 . . .	36
1978 . . .	110
1979 . . .	260

2. 1966–77 का वार्षिक औसत 153 है। 1967 से 1970 तक की अवधि में साम्प्रदायिक तनाव बहुत अधिक था। फिर भी, संगठित प्रयासों तथा लगातार निगरानी से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इसके कारण साम्प्रदायिक झगड़ों तथा मौतों की संख्या में भी काफी कमी हुई और वर्ष 1972 से 76 के दौरान मारे गए व्यक्तियों का वार्षिक औसत केवल 60 था । 1978 और 1979 के दौरान साम्प्रदायिक झगड़ों की घटनाओं में फिर वृद्धि हो गई जिसके कारण 1977–79 का वार्षिक औसत बढ़ कर 135 हो गया ।

PROF. MADHU DANDAVATE: Mr. Speaker, Sir, the statement that has been laid on the Table of the House gives the number of persons killed from 1966 to 1979.

I would like to know from the Home Minister whether it is true or not that looking at the very same figure which he has given, it is wrong to politicalise the issue of communal disturbances and communal riots but to admit the fact that it is the anti-social communal elements which are responsible for this irrespective of the set-up of the Government. From the figures given, it is clear that it is wrong to attribute the communal disturbances and riots to any particular party. Therefore, is it not a fact that, from the figures that

you have given, in the socalled "dynamic decade", the annual rate of death is 170 whereas in 1977 to 1979, you yourself admitted that it was 135. Will the Government rise above the political parties and take all the secular forces into confidence and try to see that the communal disturbances are prevented?

श्री जैल सिंह : माननीय सदस्य की आशंका दुरुस्त नहीं है । 1966 से ले कर 1979 तक के जो आंकड़े हैं उन को देखने से पता चल सकता है कि जो ज्यादा घटनाएं हुई हैं वे 1966 से ले कर 1970 तक हुई हैं। रांची, बिहार में हुई, मालेगांव, महाराष्ट्र आदि में हुई हैं । रांची में 184 मर्डर हुए और उसके लिए रघुबर दयाल कमिशन बनाया गया था । दूसरे के लिए रघुबर दयाल कमिशन बनाया गया था । उस वक्त बिहार में जो सरकार थी वह एस वी डी की थी। ला एण्ड आर्डर का जो विषय है यह स्टेट सबजक्ट है। उस वक्त सेंटर में सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की थी लेकिन स्टेट में जो सरकार थी वह मिली जुली थी, जिस को खिचड़ी सरकार कहते हैं वह थी । यह 1967 की बात है । 1968 में नागपुर में 26 मर्डर हुए। मेरठ में 16 हुए। मुजफ्फरनगर में 7 हुए। करीमगंज असम में 7 हुए । तब उत्तर प्रदेश में जो मर्डर हुए, उस वक्त भी वहां एस वी डी की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह जी उसके मुख्य मंत्री थे ।

PROF. MADHU DANDAVATE: Some Members might have asked him those questions.

श्री जैल सिंह : मेरे सत्कार सहयोगी आपने जो सप्लीमेंटरी किया उसमें आपने यही कहा कि यह जो आंकड़े दिखाये गये हैं उनमें सियासी दलों को बताया गया है, कम्युनल बात नहीं बताई गई । मैं उसी का विवरण आपको दे रहा हूं ।

इसी तरह से 1969 में गुजरात में रायट हुए उसमें 79 मर्डर हुए और जगन्नाथ रेड्डी कमीशन वहां बैठाया गया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रमशः 18, 17 और 16 मर्डर हुए । 1970 में भिवानी, जलगांव... (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, मेरी दिक्कत यह है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं मिल रहा है, और जो सवाल नहीं पूछा उसका वह जवाब दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी कीजिए ।

प्रो० मधु दंडवते : अगर होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं तो हम हर बार सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि सप्लीमेंटरी भी लिख कर देने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सप्लीमेंटरी कीजिए ।

(Interruptions) **

MR. SPEAKER: Nothing is to be recorded without my permission.

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं होम मिनिस्टर से, मेरा सवाल है कि जितने फिरकापरस्ती की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आगे चल कर, जैसे कई साल पहले कश्मीर में नेशनल इंटेगरेशन काउन्सिल का एक जलसा हुआ था जिसमें कई फैसले हुए थे और उन फैसलों पर अमल करने का तय हुआ था, इस तरह से सियासी सवाल पैदा करने के बजाय सभी शक्तियों को साथ ले कर इस सवाल को हल करने की आप कोशिश करेंगे कि नहीं ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मेम्बर साहब के इस सुझाव से सहमत हूं । हम नेशनल इंटेगरेशन काउन्सिल, जो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई थी, काम नहीं करती थी, उसको रिवाइव करने के लिए सोच र हैं। हमारा इस बात पर भी ध्यान है कि सिर्फ डंड से नहीं बल्कि परसुएशन और निगोशियेशन्स से हम इस मामले को सुधारेंगे ताकि नेशनल इंटगरेशन के लिए यह चीजें अच्छी रहें ।

श्री भगतभाई बरोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह 1977 से 1979 के जो आंकड़े दिये गये हैं क्या उनकी जांच में यह बात पायी गई कि आर० एस० एस० जैसी संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं की वहां चलती हुई सरकार, और यहां भी सरकार, में उनके लोग बैठे हुए थे उनका साथ ले कर ज्यादा से ज्यादा जमशेदपुर, अलीगढ़ आदि इन इलाकों में हुए दंगों में उनका हाथ रहा और सरकार की आंख मिचौनी रही ? क्या यह बात सही है ?

श्री जैल सिंह : ज्यादातर जो फिरकेवाराना फसाद हुए वह 1978 और 1979 में हुए । इसके लिए सरकार पिछली बातों के लिए कोई और कमीशन बठाये या कोई जानकारी करे इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और आइन्दा ऐसे दंगे फसाद न हों इस बारे में उपाय किए जायेंगे ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अलीगढ़ में जनता सरकार के जमाने में जो बलवा हुआ, वह बराबर एक साल तक उस बलबे को कण्ट्रोल करने में फेल रही, जो आज तक हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ।

**Not recorded.

क्या यह सही है कि अलीगढ़ के उस बलवे के लिए मि० नवमान पूरे-पूरे जिम्मेदार थे, जो जनता पार्टी के प्रैजिडेंट थे ? क्या यह भी सही है कि अलीगढ़ और जमशेदपुर के बलवों में माइनारिटी का जितना भी नुकसान हुआ वह पी ए सी और सी आर पी के पहुंचने के बाद हुआ रायट्स को कण्ट्रोल करने के लिए एक रायट फ़ोर्स बनाने के बारे में बराबर प्रोपोज़ल आ रहे हैं, जिसमें माइनारिटी कम्युनिटी को बराबर रिप्रेज़ेन्टेशन हो । क्या सरकार इस तरफ भी तवज्जुह दे रही है ?

श्री ज़ैल सिंह : यह सही है कि अलीगढ़ में दो बार, अक्तूबर और नवम्बर में, रायट्स हुए । अक्तूबर में 12 और नवम्बर में 16 कत्ल हुए, और जो जख्मी हुए, उनकी निगती 47 और 32 थी । यह मामला गम्भीर है । इस पर हम विचार करेंगे और इसके पीछे क्या कारण थे, ये रायट्स कैसे हुए, इसकी जानकारी भी करेंगे ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : मैंने रायट फ़ोर्स बनाने के प्रोपोज़ल के बारे में भी पूछा है । उसका जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री ज़ैल सिंह : इस पर भी ग़ौर किया जा सकता है ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, while it is true that in these communal disturbances, the members of the different communities suffer to a greater or lesser degree, nevertheless is it not a fact that this phrase 'communal disturbance' has become only a 'polite phrase' to hide the fact—the grim fact —and the reality that the overwhelming number of victims of these communal disturbances belong to the minority community?

Sir, I want to know about this categorically, because, he has given the number of deaths and so on. But, Sir, there is no way of knowing from this that actually the members of the minority community have been overwhelmingly the victims of these atrocities and riots. So, Sir, I want to know from him categorically whether that is a fact or not. Secondly I want to know..(Interruption) If it is so obvious, don't call them communal disturbance. They are anti-muslim pogroms. Atrocities are being carried out and they are categorised under the polite name of 'communal disturbances'. Secondly, I would like to know what action, if any, has been taken against those members, officers and others, of the Police force who have been found to be guilty either of excesses or lapses or of dereliction of duty or even conniving at some of these so-called disturbances which have taken place. What action has been taken against such police officials on whom nowadays nobody has got any confidence whatsoever, that they will be able to deal with these situations?

श्री ज़ैल सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी के लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ, मगर सरकार के पास जो आंकड़े आये हैं, उनमें यह नहीं बताया गया कि कौन से मजहब के लोगों को नुकसान पहुंचा और कौन से लोग थे, जिन्होंने उनको मारने में ज्यादा काम किया । लेकिन कमीशन की रिपोर्टों को पढ़ने से इसकी जानकारी की जा सकती है । मैं यकीन दिलाता हूं कि हम यह जानकारी भी करेंगे कि क्या सिर्फ माइनारिटी को तो ही नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि

In 1979, there were 297 incidents of a communal nature and 912 cases of communal tension. The year witnessed 8 major communal riots. There were two riots in Jamshedpur in April and August. There were two riots in Aligarh in May and June.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता । दो क्वाइंट्स मैंने पूछे हैं एक माइनारिटीज के बारे में और एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ।

श्री ज़ैल सिंह : मैं उनके दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि हमारी सरकार अभी-अभी आई है, इस बात की हम ने जानकारी नहीं की । हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस वाले उसमें शामिल थे या नहीं थे और कैसे उन का हाथ रहा है, मगर मैं यह यकीन दिलाता हूं, हम इस बात पर गौर करेंगे ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जनता सरकार और लोकदल सरकार के समय बहुत ज्यादा रायट्स हुए हैं हमारे देश में और उस समय हमारी जानकारी है.....(व्यवधान).....

चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो फैक्ट्स हैं उन को मान कर चलें ।

उस समय हमारी जानकारी है कि कम्यूनल फोर्सेज हमारी सरकार के अंदर थीं । तो क्या वर्तमान सरकार ऐसी जो ताकतें हैं जिन में कि आर एस एस और जमायते इस्लामी की संस्थायें हैं जो कि ज्यादा तरीके से रायट्स को स्प्रेड अप करती हैं उन को बैन करने के लिए इम्मीडिएटली कदम उठाएगी ।

श्री ज़ैल सिंह : इस मामले में हम ने बैन करने के लिए तो कोई गौर नहीं किया मगर सरकार का यह पोख्ता इरादा है कि कम्यूनल फोर्सेज किसी भी शक्ल में हों, किसी भी नाम से हों, उन को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और उस के लिए सख्त कदम उठाए जायेंगे ।

जो पिछली सरकार के वक्त में हुआ वह इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं थी और गवर्नमेंट में जो मंत्रिगण थे वे सभी के सभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते थे ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं एक छोटे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 मील दूर अलीगढ़ में पिछले दो वर्षों में हर महीने दंगे होत रहे, हर महीने वहां पर कर्फ्यू लगता रहा, फिर भी सरकार उस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई ? क्या पुलिस की अक्षमता थी या राजनैतिक नेतृत्व की नपुंसकता थी जिस से जनता पार्टी क कृष्णकान्त जैसे मेम्बरों के कहने क बावजूद भी कि वहां जनता पार्टी के सभापति नवमान ऐसे व्यक्तियों ने दंगे कराए, दंगे नहीं रुक ? क्यों ? नपुंसकता राजनैतिक नेतृत्व की थी या पुलिस की अक्षमता ? इस का स्पष्ट उत्तर दीजिए ।

श्री ज़ैल सिंह : स्पष्ट उत्तर तो इस का यही है कि इस में इतना कुसूर पुलिस का या एंडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था जितना बाहर से मदाखलत की और सरकार में कई तरह के तत्व जो शामिल थे वह किसी न किसी की मदद करते थे और उन्होंने पुलिस को डिमारेलाइज कर दिया था जिस की वजह से ये फसाद होते थे ।.....(**व्यवधान**).....

मगर, स्पीकर साहब, मैं एक प्रार्थना करूंगा— यह जो क्वेश्चन आया है यह पिछली सरकार के जमाने का है, इस लिए जो सही बात है वह तो बतलानी पड़ेगी । मगर जब बतलाता हूं, तो वे समझते हैं कि उन को उत्तर नहीं मिला, ऐसी हालत में उत्तर और किस तरह से मिल सकता है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मोहतरिम स्पीकर साहब, जो आदादो-शुमार दिये गये हैं, वे यह बतलाते हैं कि जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान बिहार में बे-पनाह इजाफा हुआ । क्या यह हकीकत नहीं है कि नेशनल इन्टीग्रेशन कान्सिल ने यह सिफारिश की थी कि अगर किसी जगह पर कोई बड़ा दंगा या फिसाद होता है तो उस के लिए वहां क कलैक्टर और वहां के बड़े पुलिस अफसर को जिम्मेदार करार दिया जायगा ? क्या यह हकीकत नहीं है कि जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीरें-आजम ने ऐलान किया था कि वह इस उसूल को नहीं मानते हैं ? क्या यह हकीकत नहीं है कि इन बातों की वजह से पुलिस अफसरान के अन्दर इस किस्म की चीज पैदा हो गई थी जिस की वजह से फिसादात में बे-पनाह इजाफा हुआ ? क्या यह हकीकत नहीं है कि उस वक्त यह मुतालबा किया गया था कि पुलिस के अन्दर अकलीयतों की, खास तौर पर मुसलमानों की, तादाद को बढ़ाया जाय ? अगर ऐसा था तो इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत का क्या रवैया है ? क्या अकलीयतों और मुसलमानों की तादाद को मुनासिब तौर पर पुलिस फोर्स में बढ़ाने के लिए इकदामात उठाये जायेंगे ? मैं चहूंगा कि वजीर साहब साफ और वाजा तौर पर इस का जवाब दें ।

شری جی - ایم - بنات والا :

محترم اسپیکر صاحب، - جو اعداد و شمار دئے گئے ہیں - وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دوران فسادات میں بے پناہ اضافہ ہوا - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کونسل نے یہ سفارش کی تھی کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بڑا دنگا یا فساد ہوتا ہے تو اس کے لئے وہاں کے کلیکٹر اور وہاں کے بڑے پولیس افسر کو ذمہ دار قرار دیا جائیگا - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس اصول کو نہیں مانتے ہیں - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے پولیس افسران کے اندر اس قسم کی چیز پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ

سے فسادات میں بے پناہ اضافہ ہوا - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پولس کے اندر اقلیتوں کی خاص طور پر مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے - اگر ایسا ہوا تو اس سلسلہ میں موجودہ حکومت کا کیا رویہ ہے - کیا اقلیتوں اور مسلمانوں کی تعداد کو مناسب طور پر پولس فورس میں بڑھانے کے لئے اقدامات اٹھائے جائینگے - میں چاہوں گا کہ وزیر صاحب صاف اور واضح طور پر اس کا جواب دیں -]

श्री जैल सिंह : मैं वाजा तौर पर इस का जवाब देता हूं । तीन-चार प्रश्न तो जो आप ने इस तरह से किये हैं कि "क्या यह सही नहीं है, क्या यह सही नहीं है," मैं यह कहूंगा कि जिन बातों के लिए आप ने कहा है कि सही नहीं हैं, मैं कहता हूं कि वे सही हैं । दूसरी बात जो आप ने पूछी है—क्या अकलीयतों की, खास तौर पर मुसलमानों की पुलिस में तादाद बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी, इस के लिए मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार माइनारिटीज का खास तौर पर ध्यान रख कर कि उन पर किसी किस्म का जुल्म न हो, हर मुनासिब कदम उठायगी और यह बात भी यकीनी तौर पर आप को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि माइनारिटीज हों या मैजोरिटी हो, हिन्दुस्तान के हर शहरी को एक ही तरह से ट्रीट किया जायगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्पीकर साहब, मेरी बात रह गई । नेशनल इन्टीग्रेशन कउन्सल की रिकमेन्डेशन के बार में कुछ नहीं कहा गया, वह उस को मानते हैं या नहीं ?

[شری جی - ایم - بنات والا :

اسپیکر صاحب - میری بات رہ گئی - نیشنل انٹیگریشن کونسل کی دی کمنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا - وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں ؟]

श्री जैल सिंह : मैंने कहा है—आप का कहना बिलकुल दुरुस्त है । नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सल का जो फैसला था या जो सिफारिश थी, उस सिफारिश को जनता सरकार ने नहीं माना . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री चरण सिंह : जो जवाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, उस जवाब के मुताबिक ये आंकड़े सही है या नहीं, जिन को मैं पढ़ कर सुनाता हूं । जैसा आप ने कहा है कि जनता गवर्नमेंट के जमाने में ज्यादा रायट्स हुए और हमारे माननीय मिंत्र ने भी यही फरमाया है, लेकिन वाक्या यह है कि जो आप का जवाब है, वह ठीक उस के उलट है । होम मिनिस्टर साहब कहते हैं. . . . . (**व्यवधान**) . . . .

AN HON. MEMBER: On a point of order.

MR. SPEAKER: You cannot raise any point of order during Question Hour.

श्री चरण सिंह : सन् 1969 में 519 इन्सीडेन्ट्स हुए । सन् 1970 में. . . . . .

MR. SPEAKER: This has been given in the answer.

श्री चरण सिंह : उस को छिपा कर कहा जा रहा है . . . . . (**व्यवधान**) . . . . . कहा गया है कि 1977–78 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्सीडेन्ट्स ज्यादा हुए । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो जवाब दिया गया है. . . . . (**व्यवधान**) . . . . . आप जरा उस जवाब को सुनने की कोशिश कीजिए . . (**व्यवधान**) . . . . .

MR. SPEAKER: This is not the way to interrupt. Please sit down. It is for the Home Minister to explain; you have not to explain these things..... (**व्यवधान**) . . .

MR. SPEAKER: Order, please. This is not the proper way to function in the House.

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय होम मिनिस्टर ने यह फरमाया कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तब रायट्स ज्यादा हुए इन्सीडेंट्स ज्यादा हुए । उन्होंने जो यह जवाब

दिया है ठीक इसके विपरीत है और मैं आप को पढ़ कर आंकड़े सुना देता हूं :

1977 में 188 इन्सीडेंट्स हुए
1978 में 230 " "
जब कि 1969 में 519 " "
1970 में 521 " "
1971 में 321 " "
1972 में 240 " "
1973 में 242 " "

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका जो जवाब दिया हुआ है, उसके खिलाफ. क्योंकि सबके पास जवाब नहीं है, होम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं । तो क्या यह क्वेश्चन आफ़ प्रिविलेज नहीं है कि वे गलत बयानी कर रहे है ? (व्यवधान).. :

श्री जैल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मेम्बर चौधरी चरण सिंह ने जो आंकड़े मैंने दिये हैं, उनके बारे में कहा है । मैं उनकी शंका को दूर करना चाहता हूं । आप ने मेरे दिये हुए आंकड़ों से ही यह साबित करने की कोशिश की कि इसमें हमारा ज्यादा कसूर है । .. (व्यवधान) ... गवर्नमेंट के ये आंकड़े हैं । पहले मेम्बर साहबान ने कहा था कि मैं ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया । मैंने उनको बताया था कि कैसे कैसे यह हुआ :

1966 में 45
1967 में 251
1978 में 133
1969 में 674
1970 में 298

ये जो आंकड़े हैं, ये सही बोलते है लेकिन इस में कसूर किस का है । इन सालों में जरा ग़ौर से सुनिये, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रान्तों में जो सरकारें थीं वे यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकारें थीं और उन्हीं सरकारों का यह मामला है । स्पीकर साहब. चौधरी चरण सिंह जी को यह बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार कायम हुई 1978 में वह रही और 1979 में जनता (एस) की सरकार हो गई जब कि खुद चौधरी साहब प्रधान मंत्री थे । अब आप देखिये कि इस जमाने में ज्यादा मर्डर हुए हैं, या उस जमाने में ज्यादा मर्डर हुए हैं जबकि इन भाईयों की सरकारें थीं ।

MR. SPEAKER: Now question 39.

श्री सूरज भा : हरिजन भी मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

श्री रशीद मसूद : हैदराबाद में कितने रायट्स पिछले महीनों में हुए हैं ।.... (व्यवधान)

[شری رشید مسعود - حیدرآباد میں کتنے رائٹس پچھلے مہینے میں ہوئے ہیں - ......(وودھان)]

MR. SPEAKER: No, not now. I have gone over to the next question.

श्री सूरज भान : रायट्स में हरिजन भी मरे हैं ।

MR. SPEAKER: It is all right. Now I have already gone over to the next question. Now Question 39.

Release of Salt Land for Construction of Road in Bhandup Village in Bombay

*39. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Maharashtra Government have approached the Salt Commissioner, Ministry of Industry for release of Salt land for the purpose of constructing an approach road for Bhandup Village in Bombay suburbs;

(b) if so, when and the details thereof; and

(c) whether the Central Government have directed the Salt Commissioner to hand over the land to the Maharashtra Government?

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) and (b). Yes, Sir. The Government of Maharashtra made a proposal to the Salt Commissioner in September, 1979 for transfer of Salt Department lands at Bhandup, forming part of Survey Nos. 21, 246 and 275 for construction of a road from Datar Colony to Bhandup level crossing by the Bombay Municipal Corporation.

(c) The matter is under consideration.